कि अगर मुम्बई ब्लास्ट्स नहीं होते, तो आने वाली जो बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में थी, वह इसी नॉन-पेपर के बेस पर होती। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत गंभीर बात है। सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उनका कश्मीर के बारे में क्या इरादा है? क्या वे pre-1953 की position को बहाल करना चाहते हैं? क्या de-militarise करना चाहते हैं? यानी स्थिति क्या है? कश्मीर के बारे में आज हम कहां खड़े हैं, यह बताया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : कश्मीर के ऊपर डिसकशन नहीं हो रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): पार्लियामेंट में खड़े हैं।

डा0 मुरली मनोहर जोशी : पार्लियामेंट में नहीं खड़े हैं। पार्लियामेंट ने तो जो प्रस्ताव पास किया था, उसके मुताबिक एक-एक इंच ज़मीन वापस लेनी थी। वहां आप खड़े होते, तो मुझे बहुत खुशी होती। ...**(व्यवधान)**...

श्री संतोष बागड़ोदिया : आप खड़े हैं सर !

डा0 मुरली मनोहर जोशी : मैं तो खड़ा हूं, मैं तो उसी जगह खड़ा हूं। सवाल आपका है, इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इस पर सरकार अपनी स्थिति साफ करे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : ठीक है, आपने कहा है, if the government wants to respond, it will. Next is Prof. Alka Balram.

Evaluation of examination papers of the Chowdhary Charan Singh University of Meerut by middle passed children

प्रो0 अलका क्षत्रिय (गुजरात) : उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में चौधरी चरण सिंह युनिवर्सिटी के B.A., B.Sc., M.Sc., BBA और MBA के युनिवर्सिटी परीक्षा के जो पेपर्स हैं, पांचवीं और आठवीं पास बच्चे वे पेपर्स चैक कर रहे हैं - ऐसा पिछले वीक हमने इंडिया टी.वी. पर देखा। इसके लिए पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है। उस गिरोह से जब पूछा गया कि ये पेपर्स आपको कौन देता है, आपके पास कहां से आए? तो उन्होंने जिसका नाम लिया, वह मेरठ युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का बेटा है, जिसको ये पेपर्स चैक करने का contract दिया गया है। वह वे पेपर्स दो रुपए और पांच रुपए में चैक करवाता है और सिर्फ पांचवीं और आठवीं पास बच्चे उन पेपर्स को चैक कर रहे हैं, जिनको B.A., B.Sc., M.Sc. की full form तक मालूम नहीं है। जो बच्चे पूरे साल मेहनत करके, इम्तिहान देकर अच्छा रिज़ल्ट लाना चाहते हैं, उनके पेपर्स ऐसे लोगों से चैक करवा दिए जाते हैं। उनको पढ़ाने के लिए उनके parents कितनी मज़दूरी करके, अपना पेट काटकर उनको पढ़ाते हैं, खर्चा करते हैं। महोदय, इससे भी आगे, जब युनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के वहां छापा मारा गया, तो उनके घर से करीब पचास हज़ार कॉपियां बरामद हुई हैं। अब ये कॉपियां एक-दो कॉपियां तो हैं नहीं। ये कहां से आई, किसमें लोड करके आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं, उसकी जांच भी होनी चाहिए। हालांकि यह राज्य से जुड़ा मामला है, लेकिन पूरे देश के विद्यार्थियों के साथ क्या ऐसा होगा? यह तो भावी नागरिकों का भी मामला है, इसलिए

मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूं कि सरकार इस मामले की जांच करवाने के लिए आदेश दे और वहां के राज्यपाल से भी कहे कि वे इसकी पूरी रिपोर्ट मंगाएं और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनके against कार्यवाही की जाए, धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : सर, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी इससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पर्चों की जांच बच्चों से कराए जाने का यह जो मामला प्रकाश में आया है, यह मामला केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, बल्कि शर्मनाक भी है।

महोदय, परीक्षा से पहले पर्चे लीक होने का मामला तो बहुत बार प्रकाश में आता रहता है, कई युनिवर्सिटीज़ का भी और कई संस्थाओं का भी, लेकिन पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां परीक्षा के बाद उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच पांचवीं और छठी क्लास के बच्चों के द्वारा करवाई जा रही है। सबसे पहला जो पर्चा सामने आया, वह फिज़ियोथेरेपी का था और जो बच्चे जांच कर रहे थे, उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया गया। उनसे पूछा - तुम कौन सी क्लास तक पढ़े हो? उन्होंने कहा - पांच तक। पूछा - फिज़ियोथेरेपी का शब्द सुना है? उसका अर्थ जानते हो? उन्होंने कहा - नहीं। तो क्या कर रहे हो? बोले - पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं। जब तुम फिजियोथेरेपी का अर्थ नहीं जानते हो, तो जांच कैसे कर रहे हो, नम्बर कैसे लगा रहे हो? वे बोले कि हम लिखाई देख लेते हैं, जिसकी लिखाई सुन्दर होती है, हम उसको ज्यादा नम्बर दे देते हैं और हम उत्तर की लम्बाई भी देख लेते हैं। जिसका उत्तर ज्यादा लम्बा होता है, उसको ज्यादा नम्बर देते हैं। उपसभापति जी, किसी छात्र के भाग्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो सकता है, वह इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। फिजियोथेरेपी पढ़ने वाला बच्चा कितनी पढ़ाई करता होगा, मेहनत करता होगा और कड़े परिश्रम के बाद पर्चा देता होगा और उस पर्चे की जांच पांचवी-छठी के बच्चे से करवाई जाएगी और उससे उसके पास और फेल का फैसला होगा, इसकी कल्पना न वह कर सकता है और न हम कर सकते हैं। अभी अल्का जी ने यहां पर बोलते हुए कहा कि यह राज्य का मामला है। उपसभापति जी, यह राज्य का मामला नहीं है। एक संस्था यूजीसी है, युनिसर्विटी ग्रांट्स कमीशन, यह एक्ट के द्वारा बनी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक। उस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक की धारा-12, उस आयोग पर यह जिम्मेदारी डालती है। धारा-12 में उसके कर्त्तव्यों की व्याख्या है, बाकी कर्त्तव्यों के अलावा यह कर्त्तव्य भी आयोग को सौंपा गया है कि वह परीक्षा और शिक्षा के स्तर में सुधार करेगा। परीक्षा के स्तर में सुधार करना, उसकी लगातार निगरानी करना, यह यूजीसी का काम है। हिन्दुस्तान की हर युनिवर्सिटी, हर विश्विद्यालय युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से अनुदान लेता है और वे उसके मातहत हैं। इसलिए इसे राज्य का मामला कहकर खारिज कर देना सही नहीं होगा। महोदय, मैं शून्यकाल में उठाए गए इस मामले के माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले का तुरंत गंभीरता से नोटिस ले, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे, अगर इस युनिवर्सिटी के खिलाफ कार्यवाही करनी बनती है तो वह कार्यवाही भी करे, लेकिन आज छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वह बंद होना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि साईंस की पढ़ाई पढ़ो और साईंस की पढ़ाई में फिजियोथेरेपी आती है, उनकी परीक्षा की जांच पांचवीं और छठी कक्षा के बच्चों से करवाओ तो इससे ज्यादा शर्मसार करने-

कभी और कोई घटना नहीं हो सकती। यह मामला तो सामने आ गया, जो सामने नहीं आए हैं, उनके बारे में कल्पना करिए। यह कोई एक दिन की बात नहीं है। एक दिन के बाद कुछ कापियां, करीब दस हजार कापियां मेड के घर से निकलीं। उसके बाद कुछ कापियां मैदान में पड़ी हुई मिलीं। यह मामला कहां जा रहा है? यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, श्रीमती सुषमा जी द्वारा उठाए विषय से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उपसभापति महोदय, श्रीमती सुषमा जी द्वारा उठाए विषय से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री कलराज मिश्र: उपसभापति महोदय, श्रीमती सुषमा जी द्वारा उठाए विषय से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

SHRIMATI MAYA SINGH (Uttar Pradesh): Sir, we all associate ourselves with this issue.

श्री अजय मारू (झारखंड) : उपसभापति महोदय, श्रीमती सुषमा जी द्वारा उठाए विषय से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : उपसभापति महोदय, श्रीमती सुषमा जी द्वारा उठाए विषय से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

डा0 मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : सर, मेरा इस बारे में एक सुझाव है और मैं श्रीमती सुषमा जी की बात का समर्थन करता हूं। जो इन्होंने बात कही है कि यूजीसी को इसपर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और वहां की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए, कैन्सल किया जाना चाहिए। साथ ही यह जांच भी की जानी चाहिए कि उस युनिवर्सिटी द्वारा दी गई डिग्री की क्या स्थिति होगी? यह कोई सामान्य मामला नहीं है। इसके बाद उस विश्वविद्यालय की डिग्रीज पर अन्तर्राष्ट्रीय चिह्न लग जाता है। इसलिए इन्टर युनिवर्सिटी बोर्ड और यूजीसी को परीक्षाओं और डिग्रीज के मामले में तत्काल कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही जो तमाम दोषियों के बारे में मांग की गई है, वह तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, हमारा नाम नहीं आता है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपका नाम आ जाएगा।

श्री रुद्रनारायण पाणि : हमको विषय उठाने के लिए मौका नहीं देते हैं। ...(व्यवधान)...महत्वपूर्ण विषय है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपका नाम आ गया, आपका नाम आ गया। ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : इसलिए तो मैं कह रहा था कि जो रवि शंकर जी का विषय है और जो विषय अल्का जी ने उठाया है, इस आधार पर तत्काल * की जाए।

श्री उपसभापति : * यह रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, जो विषय सुषमा जी और अल्का जी ने उठाया है, यह देश के उन नागरिकों और बच्चों का भविष्य है, जो स्वयं देश के भविष्य है, इसलिए यह मामला बहुत गंभीर मामला है। मेरा यह निवेदन है और मैं सुषमा जी की बात से सौ प्रतिशत सहमत हूं कि किसी राज्य या सरकार या दलों से ऊपर उठकर, इस पर विचार करना चाहिए। यह मामला यूजीसी का है और यह ऑटोनोमस बॉडी है तथा मैं शिक्षा विभाग से आता हूं। उस बॉडी पर सरकारों का नियंत्रण नहीं होता है। अगर होता है, तो उसमें गवर्नर्स जरूर चांसलर होते हैं और उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करती है। इसलिए अल्का जी, इसमें सुधार कर लीजिए। ...(व्यवधान)... अलका जी, इन बातों को छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है, जिसकी जांच बड़े ढंग से करानी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि यह उन बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो इस देश का भविष्य हैं, यदि उनका भविष्य खराब होगा, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसे गहराई से और गंभीरता से लिया जाए।

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं भी अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री उपसभापति : यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड मैंटेन करने की जिम्मेदारी UGC की है और UGC को चाहिए कि वह इसे गंभीरता से ले और इसकी जांच कराए।

Need to take effective measures to tackle the drought situation in Bihar

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, देश के कई भागों में वर्षा होने के कारण भयंकर बाढ़ आ गई है और पिछले कई दिनों से स्थिति बहुत नाज़ुक है, लेकिन इस वर्ष बिहार में स्थिति बिल्कुल विपरीत है और वहां सुखाड़ की स्थिति है, अकाल की स्थिति है। अब यह सुखाड़ और अकाल की स्थिति का मुकाबला दो तरह से किया जा सकता है। खरीफ की बुवाई के लिए किसान को, जो पहले से नहर है, उस नहर से सिंचाई के लिए पानी दिया जाना चाहिए। सरकारी हिसाब से बताया गया है कि 37 लाख हैक्टेयर भूमि में से सिर्फ 22 लाख हैक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल लगी थी, लेकिन सुखाड़ के चलते, वह भी सूख गई है और सूख रही है और जो भी पौध, धान के लिए उगाई गई थी, वह सूख गई है। भूगर्भ जल के लिए बिहार का स्थान तीसरा है, पहले झारखंड था, तो दूसरा स्थान था। वहां का जल स्तर बहुत नीचे नहीं है, 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट पर अभी कहीं-कहीं बिहार में पानी मिलता है। तो भूगर्भ जल के लिए जो स्टेट ट्यूबवैल है, उससे जो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है और सारे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। मवेशियों के लिए जो चारे की व्यवस्था है, उस पर भी संकट आ गया है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर बिहार

---

* Expunged as ordered by the Chair.